उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में

आदेश सं. 2001 का 584 (पुराना नं. 1997 का 97)

उत्तर प्रदेश राज्य ………
अपीलार्थी

बनाम

मेसर्स फूल चंद्रा ……….
उत्तरदाता

कोरमः मानननीय सुधांशु धूलिया,
जे. माननीय आर सी खुल्बे, जे

सुश्री बीना पांडे, उत्तर प्रदेश राज्य की विद्वान स्थायी वकील/अपीलार्थी।

श्री नंदन आर्य, प्रतिवादी के अधिवक्ता।

माननीय सुधांशु धूलिया, जे. (मौखिक)

मध्यस्थता का एक मुख्य उद्देश्य सख्ती हटाकर मामलों का त्वरित प्रक्रियात्मक कानून द्वारा निस्तारण करें। इसका उद्देश्य एक फास्ट ट्रैक प्रणाली होना था। फिर भी हमारे सामने एक मामला है, जिसका एक अनूठा और उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है, क्योंकि यह लगभग 25 वर्षों से अदालतों में है!

2. 22.03.1985 दिनांकित एक समझौता ठेकेदार जो की मेसर्स फूल चंद्रा और उत्तर प्रदेश राज्य का सिंचाई विभाग, सिविल और इंजीनियरिंग कार्य के बीच निष्पादित किया गया था। बाद में पक्षों के बीच एक विवाद उत्पन्न हुआ और मामले को मध्यस्थता खंड की शर्तों के अनुसार मध्यस्थता के लिए भेजा गया, जो अनुबंध का एक हिस्सा था। मध्यस्थ ने 29.08.1994 को अपना निर्णय दिया। इसके बाद, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 30/33 के तहत निर्णय को रद्द करने के लिए एक आवेदन दायर किया गया था, जिसे अदालत ने दिनांक 10.05.1996 के फैसले और आदेश के तहत खारिज कर दिया था और निर्णय का नियम बना दिया गया था।

3. UP राज्य ने 10.05.1996 दिनांकित आदेश को चुनौती वर्ष 1997 में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के समक्ष धारा 39 के तहत एक अपील में दी, जहां यह लंबित रहा, और बाद में उत्तराखंड राज्य के निर्माण के पश्चात (जिखंड UP के से पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य खंड अलग किया गया था। पुनर्गठन अधिनियम, 2000), मामला क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के आधार पर इस न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया गया था।

4. इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने अपील को स्वीकार कर लिया 25.06.2007 दिनांकित आदेश और सिविल न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) दिनांक 10.05.1996 के आदेश को अपास्त दिया गया था और मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के निर्देशों के साथ नीचे की अदालत में भेज दिया गया था। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इस न्यायालय की खण्ड पीठ की मत थी कि विद्वान सिविल न्यायाधीश ने अपने समक्ष मौजूद मुद्दों पर विचार किए बिना मामले का फैसला "सरसरी तरीके" से किया था। आदेश 25.06.2007 को ठेकेदार (मेसर्स फूल चंद्र) ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार करते हुए अपील को स्वीकार कर लिया। ऐसा करते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया था कि उच्च न्यायालय इस आधार पर आदेश को रद्द करने में सही नहीं था कि यह "सरसरी" था। विद्वान सर्वोच्च न्यायालय का विचार था कि विद्वान सिविल न्यायाधीश ने सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार किया था। यह निम्नानुसार देखा गयाः-

> पीठ ने कहा, "हमारा उपरोक्त विचार इस तथ्य पर आधारित है कि अधिनियम की धारा 30 के तहत उठाई गई आपत्तियों पर विचार करते हुए, दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), देहरादून ने इस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर तथ्यात्मक रूप खंड निर्णय दिया था। वास्तव में, पैराग्राफ 8 (यहां ऊपर दिए गए) में उच्च न्यायालय द्वारा उजागर किए गए सभी मुद्दों पर सिविल जज (सीनियर डिवीजन), देहरादून द्वारा व्यक्तिगत रूप से विचार

> किया गया था। यह और बात है कि उपरोक्त विचार वैध और वैध रूप से तय किया गया था। सिविल जज (सीनियर डिवीजन), देहरादून द्वारा दिए गए निर्णय की वैधता का मुद्दा हमारे समक्ष विचार का विषय नहीं है। एकमात्र मुद्दा जो हमारे विचार मे आता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), देहरादून द्वारा पुनः निर्णय के लिए मामले की रिमांड उचित थी या नहीं।
>
> चूंकि, हमारा विचार है कि दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), देहरादून ने विवादित आदेश के पैराग्राफ 8 में प्रतिवादी द्वारा इंगित सभी आपत्तियों को ध्यान में रखा था, और विशेष रूप से खंड 1.45, 1.46 और 1.47, उच्च न्यायालय ने मामले को दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), देहरादून को पुनः निर्णय के लिए भेजने में उचित नहीं माना।"

5. इस प्रकार, मामले को उच्च न्यायालय में वापस नए निर्णय के लिए भेज दिया गया। जब मामला इस न्यायालय के समक्ष फिर से आया, तो इस बार इस न्यायालय की खण्ड पीठ ने अपने दिनांक 14.03.2014 के आदेश के माध्यम से अपील को खारिज कर दिया। प्रवर्तनशील भाग इस प्रकार पढ़ा जाएगा -

> "4. यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को हमारे सामने रखा। तदनुसार, अपील पर पुनः सुनवाई की जाती है। हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और प्रतिवादी की ओर से पेश वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है।
>
> 5. यह अपीलकर्ता का तर्क है कि मध्यस्थ को कारण देने की आवश्यकता थी; उसने कोई कारण नहीं बताया, और यह कि मध्यस्थ ने ऊपर निकाले गए अनुबंध के खंड 1.45,

> 1.46 और 1.47 के प्रभाव पर विचार नहीं किया। तथ्य यह है कि अपीलकर्ता की ओर से उक्त विवाद ऊपर निकाले गए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से समाप्त होता है।
>
> 6. मामला केवल अपीलकर्ता को यह उजागर करने की अनुमति देने के उद्देश्य से हमारे पास वापस भेजा गया था कि, जिन मुद्दों पर विचार किया गया था, उन पर विचार करते समय, मध्यस्थ ने स्वयं कदाचार किया। इस तरह का कोई तर्क नहीं दिया गया है। हम, तदनुसार, अपील को खारिज करके समाप्त करें।"

6. इस बार उत्तर प्रदेश राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय का मामलामाननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 22.09.2015 के माध्यम से अपील को फिर से स्वीकार कर लिया और मामले को निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ फिर से इस न्यायालय में भेज दिया गयाः-

> विवादित आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.2007 को पहले ही पारित कर दिया गया था, को उपर्युक्त अवलोकन के साथ इस आधार पर अपास्त दिया गया था कि दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), देहरादून ने पहले ही उन मुद्दों पर निर्णय दे दिया था जो उच्च न्यायालय के समक्ष उठाए गए थे, और इस तरह, उच्च न्यायालय के लिए मामले को फिर से निर्णय के लिए दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग), देहरादून को भेजना उचित नहीं था।
>
> इस न्यायालय द्वारा दिनांक 12.02.2014 के अपने आदेश में दर्ज की गई स्पष्ट टिप्पणियों के बावजूद, उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी पक्षों द्वारा उसके समक्ष उठाए गए मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया है। इस मामले को ध्यान में रखते हुए, एक बार फिर मामले को उच्च न्यायालय में वापस भेजा जा

> रहा है, जिससे प्रतिद्वंद्वी दलों द्वारा गुण-दोष के आधार पर उठाए गए मुद्दों पर विचार करने और कानून के अनुसार उस पर निर्णय देने की आवश्यकता होगी। ऐसा करते समय, हम दिनांक 14.03.2014 के विवादित आदेश को रद्द कर देते हैं। पक्षकारों को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से 03.11.2015 को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।
>
> अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों में किया जाता है "।

7. इन परिस्थितियों में न्यायनिर्णयन के लिए इस न्यायालय के समक्ष मामला आया है।

8. हमने पार्टियों को विस्तार से सुना है।

9. यह मध्यस्थता अधिनियम 1940 के खंड 39 के तहत एक अपील है एक आदेश के विरुद्ध जिसके द्वारा न्यायालय ने मध्यस्थता निर्णय को अपास्त कर अस्वीकार कर दिया है, और निर्णय को न्यायालय का नियम बना दिया है।

10. निर्णय को अलग रखने के लिए आधार दिए जाते हैं। पुराने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की खंड 30 में, जो निम्नानुसार हैः-

> "30. निर्णय अलग रखने के लिए आधार। निम्नलिखित में से एक या अधिक आधारों को छोड़कर किसी भी निर्णय को रद्द नहीं किया जाएगा, अर्थात्ः-
>
> (ए) कि एक मध्यस्थ या अंपायर ने खुद को या कार्यवाही को गलत तरीके से संचालित किया है।
>
> (ख) कि न्यायालय द्वारा मध्यस्थता को निरस्त करने वाले आदेश के जारी होने के पश्चात या खंड 35 के से मध्यस्थता कार्यवाही अमान्य हो जाने के पश्चात कोई निर्णय दिया गया है;

> (ग) कि कोई निर्णय अनुचित तरीके से प्राप्त किया गया है या अन्य रूप से अमान्य है।"

11. हमने दिनांक 29.08.1994 के निर्णय को देखा है। अनुबंध की शर्तों के अनुसार, प्रतिवादी को देहरादून के पास "खारा बिजली परियोजना" के रूप में जानी जाने वाली एक पनबिजली परियोजना का निर्माण करना था। 22.03.1985 को उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और ठेकेदार के बीच एक अनुबंध निष्पादित किया गया था। यह मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए टर्बाइनों तक पानी ले जाने के लिए एक चैनल का निर्माण था। परियोजना के पूरा होने पश्चात ठेकेदार द्वारा विभिन्न मामलों में धन की मांग की गई, जैसे कि उपकरण की क्षति के कारण ठेकेदार को हुआ नुकसान; विभाग की ओर से देरी; कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि, आदि।

12. इस संबंध में तीन महत्वपूर्ण खंड हैं उस अनुबंध का, जिसका हम अब उल्लेख करेंगे। ये खंड 1.45, 1.46 और 1.47 हैं, जो नीचे दिए गए हैंः-

> "1.45:यदि ठेकेदार इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान के संबंध में प्रभारी अभियंता या उसके प्रतिनिधियों के किसी भी रिकॉर्ड या फैसले को अनुचित मानता है या प्रभारी अभियंता द्वारा उससे मांगे गए किसी भी कार्य को अनुबंध से बाहर मानता है। अनुबंध की आवश्यकताओं के अनुसार, ऐसे काम की मांग होने पर वह तुरंत लिखित निर्देशों या निर्णयों के लिए लिखित में मांगेगा, जिसके प्राप्त होने पर वह फैसले के रिकॉर्ड की पुष्टि करने या मांगे गए कार्य को करने के लिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ेगा और 15 दिनों के भीतर लिखित निर्देशों या निर्णयों की प्राप्ति की तारीख के बाद वह अपनी आपत्ति का आधार स्पष्ट रूप से और विस्तार से बताते हुए प्रभारी अभियंता को लिखित विरोध दर्ज करा सकता है। ऐसे विरोधों या आपत्तियों को छोड़कर जो यहां निर्दिष्ट तरीके से और बताई गई समय सीमा के भीतर रिकॉर्ड किए गए हैं, प्रभारी अभियंता के फैसले, निर्देश या निर्णय निर्णायक और

ठेकेदार पर बाध्यकारी होंगे। ठेकेदार को चित्र भेजने वाले पत्रों में निहित प्रभारी अभियंता के निर्देशों और/या निर्णयों को लिखित निर्देश या निर्णय के रूप में माना जाएगा, जो विरोध या आपत्तियों के अधीन होगा जैसा कि यहां प्रदान किया गया है।

1.46:यदि ठेकेदार खंड 1.45, में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ठेकेदार द्वारा किए गए विरोध या आपत्ति पर प्रभारी अभियंता के अंतिम निर्णय से असंतुष्ट है, तो ठेकेदार इस तरह के निर्णय पश्चात सूचना प्राप्त करने के अट्ठाईस (28) दिनों के भीतर प्रभारी अभियंता को लिखित रूप में नोटिस दे सकता है जिसमें आवश्यक है कि मामला मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाए और विवाद या अंतर 2 का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए जिसमें स्पष्ट रूप से मुद्दे पर लाभ निर्दिष्ट किया जाए। यदि ठेकेदार ऊपर निर्धारित 28 दिनों की अवधि के भीतर ऐसा नोटिस देने में विफल रहता है तो प्रभारी अभियंता का निर्णय निर्णायक और ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

1.47:प्रत्येक विवाद अंतर या प्रश्न जो किसी भी समय यहाँ के पक्षों या उस समय के तहत दावा करने वाले व्यक्ति के बीच उत्पन्न हो सकता है, इस विलेख या उसके विषय को छूने या उससे उत्पन्न होने या उसके संबंध में मुख्य अभियंता या उसके द्वारा नामित किसी व्यक्ति के मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। ऐसी किसी भी नियुक्ति पर कोई आपत्ति नहीं होगी कि नियुक्त किया गया मध्यस्थ एक सरकारी सेवक है, उसे उन मामलों से निपटना है जिनसे अनुबंध संबंधित है और सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के दौरान उन्होंने विवाद या मतभेद वाले सभी या किसी भी मामले पर विचार व्यक्त किए थे। जिस मध्यस्थ के पास मामला मूल रूप से भेजा गया है, उसका स्थानांतरण होने या उसका कार्यालय

> खाली होने या किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ होने की स्थिति में मुख्य अभियंता या तो स्वयं संदर्भ में प्रवेश करेगा या किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति उस स्थिति से संदर्भ के साथ आगे बढ़ने का हकदार होगा जिसे पूर्ववर्ती द्वारा छोड़ा गया था। इस अनुबंध की एक शर्त यह भी होगी कि उपरोक्त नियुक्त व्यक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करेगा और यदि किसी कारण से यह संभव नहीं है तो मामले को मध्यस्थता के लिए बिल्कुल भी नहीं भेजा जाएगा। उन सभी मामलों में जहां विवाद में दावे की राशि रु 50, 000 (पचास हजार रुपये) और उससे अधिक मध्यस्थ निर्णय के लिए कारण बताएगा।"

13. मान लीजिए कि सिंचाई के मुख्य अभियंता विभाग ने ठेकेदार के आदेश के अनुसार श्री सुरेश चंद्र गुप्ता को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया। दावे के दावे और आपत्तियाँ विद्वान मध्यस्थ के समक्ष प्रस्तुत की गईं। ये दावे 'ए' से 'क्यू' तक 17 शीर्षों के तहत थे। ठेकेदार के दावों और विभाग की आपत्तियों को सुनने पश्चात प्रत्येक दावे पर मध्यस्थ द्वारा अलग-अलग निर्णय लिया गया और कुल दावे की धनराशि रुपए 25, 72,944 रुपये (केवल पच्चीस लाख बहत्तर हजार नौ सौ चवालीस रुपये) के विरूद्ध रुपए 5,08,232/- (पांच लाख आठ हजार दो सौ बत्तीस रुपये) की राशि दी गई।

14. ब्याज के लिए, मध्यस्थ ने निर्णय दिया है कि निर्णय की तिथि तक 18% की दर से साधारण ब्याज निम्नानुसार हैः-

> "सभी दावों पर (" एन "को छोड़कर) रु 3, 51, 131.00 दिनांक 30.04.91 से 29.08.1994 तक (निर्णय की तिथि)

दावा "एन" पर (प्रतिभूति की वापसी और अग्रिम राशि) 2,50, 000.00 दिनांक 30.10.1991 से 29.08.1994 तक।

इसके अग्रेतर रुपए 5, 08, 232.00 पर प्रति वर्ष 6% (छह प्रतिशत) का ब्याज निर्णय की तिथि से भुगतान या डिक्री तक जो कभी भी पहले हो।"

15. दो बुनियादी आपत्तियाँ हैं जो अपीलकर्ता द्वारा निचली अदालत के साथ-साथ हमारे समक्ष भी उठाया गया। पहला यह है कि ठेकेदार (हमारे सामने प्रतिवादी) के दावे समय-बाधित थे, और इसलिए मध्यस्थ द्वारा निर्णय लेने के लिए उत्तरदायी नहीं थे, और ऐसा करके उन्होंने खुद को गलत तरीके से संचालित किया है। दूसरे, अपना निर्णय देते समय मध्यस्थ द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है।

16. खंड 1.45 और 1.46 , जिन्हें ऊपर संदर्भित किया गया है, के पढ़ने मात्र से पता चलता है कि यदि ठेकेदार द्वारा कोई मांग उठाई जानी है तो वह इंजीनियर से निर्देश या निर्णय के लिए लिखित रूप में पूछेगा और उसके बाद ऐसे निर्देश प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर वह "अपनी आपत्तियों के आधार को स्पष्ट रूप से और विस्तार से बताते हुए" इंजीनियर प्रभारी के समक्ष विरोध दर्ज कराएगा। प्रभारी का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा, लेकिन यदि ठेकेदार प्रभारी अभियंता के निर्णय से असंतुष्ट है, तो वह इस तरह के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के 28 दिनों के भीतर लिखित में नोटिस दे सकता है। प्रभारी अभियंता को कि मामला मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किया जाए। यह संक्षेप में अनुबंध के दो खंड, खंड 1.45 और 1.46 है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, इस प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है।

17. तथ्य यह है कि हमारे पास इस संबंध में प्रभारी अभियंता का कोई लिखित आदेश नहीं है और न ही ठेकेदार का कोई विरोध है। हालाँकि, हमारे पास सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता का दिनांक 19.02.1992 का आदेश है, जिसके तहत उन्होंने श्री सुरेश चंद्र गुप्ता को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया

था। उपरोक्त आदेश के मद्देनजर विरोध दर्ज कराने और इस तरह उस पर निर्णय देने की औपचारिकताओं का फिलहाल कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि यह एक स्वीकृत तथ्य है कि स्वयं मुख्य अभियंता ने ही इस मामले में मध्यस्थ नियुक्त किया था। इसलिए, एक धारणा बनाई जाएगी कि मुख्य अभियंता इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि यह एक मध्यस्थता विवाद है, क्योंकि तभी उन्होंने मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा होगा।

18. इसके अलावा, यह दलील के दावे समय वर्जित है गलत है, क्योंकि 28 दिनों की अवधि उस तिथि से शुरू होगी जब इंजीनियर प्रभारी द्वारा ठेकेदार के दावे को खारिज कर दिया गया था। माना कि ऐसा कोई औपचारिक आदेश नहीं है जिसके द्वारा ठेकेदार का दावा खारिज किया गया हो। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि ठेकेदार द्वारा 28 दिनों के भीतर आपत्तियां नहीं की गईं। इसके अलावा, मुख्य अभियंता प्रभारी का एक आदेश दिनांक 20.11.1991 और 21.12.1991 जिसमें स्वयं स्वीकार किया गया है कि कुछ प्रमुखों पर आपत्तियां की गई थीं, और इसलिए, अब मध्यस्थ नियुक्त किया गया था। मध्यस्थ की नियुक्ति अदालत के किसी आदेश से नहीं की गई थी, मध्यस्थ की नियुक्ति इंजीनियर प्रभारी स्वयं ठेकेदार द्वारा दायर एक आवेदन दिनांक 20.11.1991 पर करता है इसलिए, यह माना जाएगा कि ठेकेदार के दावे और मध्यस्थ की नियुक्ति सीमा के भीतर थी और समय बाधित नहीं थी, अन्यथा सबसे पहले अपीलकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की होती।

19. दिनांकित 19.02.1992 आदेश अनुबंध को संदर्भित करता है और फिर ठेकेदार का पत्र दिनांकित 20.11.1991, जिसमें उसने 'ए' से 'Qi.e17 तक कुछ आपत्तियां उठाई हैं जिन्हें उन्होंने अपने दिनांकित पत्र 21.12.1991 में दोहराया है कि एक मध्यस्थ नियुक्त किया जा रहा है जो श्री सुरेश चंद्र गुप्ता हैं। UP राज्य द्वारा उठाई गई आपत्तियों दिनांकित 10.05.1996 आदेश में भी कहा गया है जिसमें 'A से 'Q तक अलग-अलग शीर्षक हैं, जिन पर ठेकेदार द्वारा निश्चित राशि की मांग की गई थी।

20. अपीलकर्ता द्वारा उठाया गया दूसरा आधार खंड 1.47 के संबंध में जो कहता है किः-

> "उन सभी मामलों में जहां विवाद में दावे की राशि ₨ 50, 000 (पचास हजार रुपये) और उससे अधिक है, मध्यस्थ निर्णय के लिए कारण बताएगा।"

21. अपीलकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता यह तर्क देते हुए कि चूंकि दावा 50,000/- (केवल पचास हजार रुपये) से अधिक था, इसलिए निर्णय में मध्यस्थ द्वारा कारण बताए जाने चाहिए थे। कानून, जैसा कि पुराने मध्यस्थता अधिनियम के तहत था, यह था कि मध्यस्थ के लिए अपना निर्णय देते समय कारण बताना आवश्यक नहीं था। हालाँकि, हम महसूस कर सकते हैं कि एक अनुबंध में एक निर्धारित शर्त थी, जिसमें कहा गया था कि ₨50, 000/- (केवल पचास हजार रुपये) से ज्यादा की तुलना में, कारण दिए जाएंगे, तो कारण दिए जाने चाहिए थे।

22. आइए अब हम उन कारणों को देखें जो मध्यस्थ द्वारा अपना निर्णय देते समय सौंपा गया। हमने दिनांक 29.08.1994 के निर्णय का अवलोकन किया है। विद्वान मध्यस्थ ने ठेकेदार द्वारा उठाए गए प्रत्येक दावे और उसमें मौजूद आपत्तियों पर अपना दिमाग लगाया है। मध्यस्थ के निर्णय में ठेकेदार (इस न्यायालय के समक्ष मैसर्स फूल चंद्र प्रतिवादी) के प्रत्येक दावे (कुल 17) के गुण और दोषों पर चर्चा की गई और उसके बाद ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे मात्रं कि कितनी राशि दिया जाना चाहिए। ये विस्तृत कारण नहीं हैं और यह फिर से आवश्यक भी नहीं है। यहां देखने वाली बात यह है कि क्या उठाए गए दावों पर मध्यस्थ द्वारा दिमाग का इस्तेमाल किया गया था। हमने पाया कि यह मानदंड पूरा कर लिया गया है। यह महसूस करने के लिए कि कैसे प्रत्येक शीर्ष के तहत निर्णय दिया गया था, हम यहां दावा 'ए' का उल्लेख कर सकते हैं जो बुलडोजर के परिवहन और उसके परिणामस्वरूप नुकसान के कारण कई स्थानों पर संदर्भ-सह-जल निकासी के भंग के कारण हमें हुए नुकसान के दावे के रूप में देय भुगतान के लिए था।" इस पर मध्यस्थ का निर्णय इस प्रकार थाः-

> पीठ ने कहा, "दावेदारों ने कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यकताओं के अनुसार संदर्भ-सह-जल निकासी का निर्माण

> किया था। दावेदारों ने शुरू में प्रतिवादियों को विभागीय बुलडोजर से इसकी क्षति के बारे में सूचित किया और अपने पत्र दिनांक 21.10.86 के माध्यम से निरीक्षण का अनुरोध किया।
>
> प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि विभागीय मशीनों द्वारा संदर्भ-सह-जल निकासी को कोई क्षति नहीं हुई है और दावेदार इस संबंध में प्रभारी अभियंता के मौखिक निर्णय से संतुष्ट थे।
>
> मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद, विभागीय उपकरणों की आवाजाही के कारण संदर्भ-सह-जल निकासी की क्षति हुई है। यद्यपि दावा किया गया नुकसान अत्यधिक है। प्रतिवादियों के अनुसार मुआवजे का अनुमान रु. 58.00 प्रति मीटर उचित माना जाता है। यह मात्र ₨ 3,480.00 के लिए काम करता है जो दावेदारों के पक्ष में दिया जाता है।"

23. इसी तरह, 'बी' का दावा करें जो वन विभाग द्वारा भुगतान खदान का आवंटन न होने और परिणामस्वरूप बैरी और रेत जैसी निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता के कारण के लिए था। मध्यस्थ का निर्णय इस प्रकार थाः-

> "यह दावा वन विभाग द्वारा खदान की अनुपलब्धता के संबंध में है। जिसके कारण दावेदार निर्माण सामग्री प्राप्त नहीं कर सके और इसलिए काम की शुरुआत में 20 महीने और एक सप्ताह तक उनका श्रम और मशीनरी बेकार पड़ी रही। काम पूरा होने में अत्यधिक देरी के कारण, दावेदार ने भी दावा (दावा एल) को प्राथमिकता दी है। चूंकि यह दावा (दावा –बी) प्रारंभिक देरी के कारण भी, इसे क्लेम-एल के साथ जोड़ा जा रहा है और इसके साथ विचार किया जा रहा है।"

24. जिन कारणों को एक मध्यस्त द्वारा निर्दिष्ट किया जाना है विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय को बस यह देखना है कि क्या मध्यस्थता विवाद के प्रति सक्रिय थी और उसने अपने फैसले पर पहुंचने से

पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। मध्यस्थ के आदेश को पढ़ने के बाद, हमारे मन में बिल्कुल भी संदेह नहीं है कि प्रत्येक शीर्ष के तहत मध्यस्थ द्वारा कारण बताए गए हैं।

25. यह इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार के पुराने मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के खंड 39 की जाँच से बाहर है कि क्या मध्यस्थ एक अलग दृष्टिकोण ले सकता था। इस न्यायालय को यह देखना होगा कि क्या मध्यस्थ ने विवाद पर फैसला सुनाते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है। इसलिए इस संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को प्रतिग्रहण करना करने के लिए हम इच्छुक नहीं हैं। हमें यह नहीं दिखाया गया है कि मध्यस्थ द्वारा बताए गए कारण गलत हैं या मध्यस्थ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कानून में टिकाऊ नहीं है। इसलिए हमारे लिए निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा (भारतीय खाद्य निगम बनाम जोगिंदरपाल मोहिंदरपाल और अन्य, ए. आई. आर. 1989 एस. सी. 1263)। भारतीय खाद्य निगम (उपरोक्त) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना थाः-

> "8. तत्काल मामले में, मध्यस्थ ने मौखिक निर्णय देने का फैसला किया है, जिसका अर्थ है कि उसने अपने निष्कर्ष के कारण बताए हैं। वह ऐसे कारण देने के लिए बाध्य है या नहीं, यह एक अन्य मामला है, लेकिन चूंकि मध्यस्थ ने कारण देने का विकल्प चुना था, जब तक कि इस न्यायालय को यह प्रदर्शित नहीं किया जाता है कि ऐसे कारण गलत हैं जैसे कि कानून के प्रस्ताव या एक दृष्टिकोण जो मध्यस्थ ने लिया है, वह एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे संभवतः मामले के किसी भी दृष्टिकोण पर कायम नहीं रखा जा सकता है, तो मध्यस्थ के निर्णय को चुनौती नहीं दी जा सकती है। जैसा कि सुदर्शन ट्रेडिंग बनाम केरल सरकार, (1989) 1 जे. टी. 339 में जोर दिया गया हैः(एआईआर 1989 एससी 890) कि यदि मध्यस्थ ने खुद को या कार्यवाही को गलत तरीके से संचालित किया है या अधिकार

> क्षेत्र से परे आगे बढ़ा है तो एक अवार्ड को रद्द किया जा सकता है। वहां इसे रद्द भी किया जा सकता है जहां अवार्ड में स्पष्ट त्रुटियां हों, लेकिन ये अलग और विशिष्ट आधार हैं। अवार्ड के प्रथम दृष्टया स्पष्ट त्रुटियों के मामले में, इसे केवल तभी रद्द किया जा सकता है यदि अवार्ड में कानून का कोई प्रस्ताव हो जो निर्णय के प्रथम दृष्टया स्पष्ट हो अर्थात्, स्वयं निर्णय में ही या निर्णय किसी दस्तावेज़ में शामिल हो। चैंपसी भरा एंड कंपनी वी. जीवराज बलू स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड, (1923) 50 इंड अति.लो.अभि. 324 (AIR 1923 PC 66) में न्यायिक समिति की टिप्पणियाँ देखें"।

26. इस तरह के मामले में भारतीय खाद्य निगम (ऊपर), यह निम्नानुसार कहा गया था:

> हालांकि, मध्यस्थता की कार्यवाही को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और ऐसी प्रथा और प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए जो विवाद के उचित समाधान की ओर ले जाए और उन लोगों का विश्वास पैदा करे जिनके लाभ के लिए इन प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है। इसलिए, यह निगरानी करना कानून की अदालतों का कार्य है कि मध्यस्थ न्याय के मानदंडों के भीतर कार्य करें। एक बार जब वे ऐसा कर लेते हैं और निर्णय स्पष्ट, उचित और निष्पक्ष हो जाता है, तो अदालतों को, जहां तक संभव हो, पक्षों के फैसले को प्रभावी बनाना चाहिए और पक्षों को अपने चुने हुए निर्णायक के निर्णय का पालन करने और उसका पालन करने के लिए बाध्य करना चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में किसी को मध्यस्थ द्वारा दिए गए फैसले में न्यायालय द्वारा सुधार की गुंजाइश और सीमा को देखना चाहिए। हमें मध्यस्थता के कानून को सरल, कम तकनीकी और स्थितियों की वास्तविक वास्तविकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना चाहिए,

> लेकिन न्याय के सिद्धांत और निष्पक्ष खेल के नियमों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और मध्यस्थ को ऐसी प्रक्रिया और मानदंडों का पालन करना चाहिए जो विश्वास पैदा करेगा, न मात्र पक्षों के बीच न्याय करके, बल्कि यह समझ पैदा करके कि न्याय किया गया प्रतीत होता है।"

27. यद्यपि एक तीसरा पहलू है जो न्याय निर्णित होना चाहिए। यह विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय के संबंध में है। विद्वान मध्यस्थ ने Rs.3, 51, 131.00/- पर 30.04.1991 से 29.08.1994 (निर्णय की तिथि) तक के सभी दावों ("N को छोड़कर) पर 18% का वादकालीन ब्याज प्रदान किया है और 6% प्रति वर्ष का ब्याज Rs.5,08,232.00/- निर्णय की तिथि से भुगतान या डिक्री तक, जो भी पहले हो पर दिया गया है ।

28. हमारी मत है कि विद्वान मध्यस्थ को वादकालीन ब्याज नहीं दिया जाना चाहिए था। मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की खंड 29 निम्नानुसार हैः-

> "29. निर्णय हित - जहाँ और जहाँ तक कोई निर्णय धन के भुगतान के लिए है, न्यायालय डिक्री आदेश ब्याज में, ऐसी दर पर डिक्री की तारीख से जिसका न्यायालय उचित समझे, मूल राशि पर भुगतान किया जाना है जैसा कि निर्णय द्वारा निर्णय किया गया है और डिक्री द्वारा पुष्टि की गई है।"

29. कार्यवाही में तीन चरण होते हैं। पहला चरण विवाद की तारीख और उस तारीख के बीच की अवधि है जब मामला अंततः मध्यस्थता के लिए भेजा गया था। दूसरा चरण मध्यस्थ द्वारा अपना निर्णय देने में ली गई अवधि है और तीसरा चरण वह चरण है जिसके दौरान निर्णय न्यायालय का नियम बन जाता है। उपरोक्त प्रावधान से, यह स्पष्ट है कि मात्र अदालत ही ब्याज दे सकती है और दूसरा यह कि ब्याज मात्र डिक्री की तिथि से दिया जाना है। तीसरे चरण के समापन पर "ऐसी दर पर जो न्यायालय उचित समझे।"

30. माननीय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ के निर्णय में शीर्ष अदालत अधिशाषी अभियंता, सिंचाई, गैलीमाला और अन्य बनाम. अबनादुता जेना, में

रिपोर्ट किया गया AIR 1988 एससी 1520, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मध्यस्थता अधिनियम और ब्याज अधिनियम के साथ-साथ सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 में उपरोक्त प्रावधान पर विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले की अवधि के लिए वादकालीन ब्याज का भुगतान नहीं किया जा सकता है और न ही निर्णय कार्यवाही लंबित है। ब्याज मात्र अदालत द्वारा ही दिया जा सकता है। इसमें कहा गया हैः

> "जिन मामलों में 1978 का ब्याज अधिनियम कार्यवाही से पहले ब्याज का अधिनिर्णय लागू करता है, उन पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। वादकालीन ब्याज, अर्थात अधिनिर्णय की तिथि तक के संदर्भ की तिथि से ब्याज के संबंध में, दावेदार इस साधारण कारण से इसके हकदार नहीं होंगे कि मध्यस्थ CPC की धारा 34 के अर्थ में न्यायालय नहीं है और न ही मध्यस्थता के संदर्भ मुकदमे के दौरान बनाए गए थे। ब्याज अधिनियम, 1978 के प्रारंभ होने से पहले उत्पन्न हुए मामलों में, दावेदार कार्यवाही शुरू होने से पहले या मध्यस्थता के लंबित रहने के दौरान ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं हैं। वे मध्यस्थता कार्यवाही शुरू होने से पहले की अवधि के लिए ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि ब्याज अधिनियम, 1939 उनके मामलों पर लागू नहीं होता है और ब्याज का भुगतान करने के लिए कोई समझौता नहीं है या व्यापार का कोई भी उपयोग जिसमें कानून का बल हो या कानून का कोई अन्य प्रावधान जिसके तहत दावेदार ब्याज वसूलने के हकदार थे। वे वादकालीन ब्याज का दावा करने के हकदार नहीं हैं क्योंकि मध्यस्थ न तो अदालत है और न ही मुकदमों में मध्यस्थता के संदर्भ दिए गए थे।"

31. इस निर्णय के बाद सर्वोच्च न्यायालय मे **रायपुर केस विकास प्राधिकरण बनाम चोखामल ठेकेदारों को ए. आई. आर. 1990 एस. सी.1426 में**

रिपोर्ट किए गए फिर यह मामला **सिंचाई विभाग, उड़ीसा राज्य बनाम GC रॉय** (1992) 1 एस. सी. सी. 508 माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष आया। जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि कुछ आकस्मिकताओं वादकालीन ब्याज भी दिया जा सकता है। इसे निम्नानुसार वर्णित किया गया थाः

> "43. प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि क्या मध्यस्थ के पास वादकालीन ब्याज देने का अधिकार है, और यदि है, तो किस सिद्धान्त पर। हमें यह दोहराना चाहिए कि हम उस स्थिति से निपट रहे हैं जहां समझौता इस तरह के ब्याज के अनुदान का प्रावधान नहीं करता है और न ही इस तरह के अनुदान पर रोक लगाता है। दूसरे शब्दों में, हम एक ऐसे मामले से निपट रहे हैं जहां समझौते में ब्याज देने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। उपरोक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में, निम्नलिखित सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं:
>
> (i) धन के उपयोग से वंचित व्यक्ति जिसका वह वैध रूप से हकदार है, उसे अभाव के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार है, इसे किसी भी नाम से कहे । इसे ब्याज, क्षतिपूर्ति या नुकसान कहा जा सकता है। यह मूल विचार उस अवधि के लिए उतना ही मान्य है जब विवाद मध्यस्थ के समक्ष लंबित है, जितना कि मध्यस्थ द्वारा संदर्भ में प्रवेश करने से पहले की अवधि के लिए है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 34 का सिद्धांत है और मध्यस्थ के मामले में अन्यथा मानने का कोई कारण या सिद्धांत नहीं है।
>
> (ii) पक्षकारों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के समाधान के लिए मध्यस्थ एक वैकल्पिक रूप (इस प्रकार की फोरम) है। यदि ऐसा है, तो उसके पास पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले सभी विवादों या मतभेदों को तय करने की शक्ति होनी चाहिए। यदि मध्यस्थ के पास वाद लंबित रहने की

अवधि पर ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं है, तो दावा करने वाले पक्ष को उस उद्देश्य के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा, भले ही उसने मध्यस्थ से अन्य दावों के संबंध में संतुष्टि प्राप्त कर ली हो। इससे कार्यवाही की बहुलता हो जाएगी।

(iii) एक मध्यस्थ एक समझौते का निर्माता होता है। यह पक्षकारों के लिए खुला है कि वे उसे ऐसी शक्तियाँ प्रदान करें और उसके पालन के लिए ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करें, जैसा कि वे उचित समझें, जब तक कि वे कानून का विरोध न करें। (मध्यस्थता अधिनियम की धारा 41 और धारा 3 का प्रावधान इस बिंदु को स्पष्ट करता है)। फिर भी, समझौता कानून के अनुरूप होना चाहिए। मध्यस्थ को भी देश के सामान्य कानून और समझौते के अनुसार कार्य करना चाहिए और अपना निर्णय देना चाहिए।

(iv) वर्षों से, अंग्रेजी और भारतीय न्यायालयों ने इस धारणा पर काम किया है कि जहां समझौता निषेध नहीं करता है और संदर्भ का एक पक्ष ब्याज के लिए दावा करता है, मध्यस्थ के पास वाद लंबित रहने तक का ब्याज देने की शक्ति होनी चाहिए। थावरदास फेरुमल बनाम भारत संघ का इस न्यायालय के बाद के निर्णयों में पालन नहीं किया गया है। इसे इस आधार पर समझाया और अलग किया गया है कि उस मामले में ब्याज के लिए कोई दावा नहीं था, बल्कि केवल अनिश्चित क्षति के लिए दावा था। यह बार-बार कहा गया है कि उक्त निर्णय की टिप्पणियों का उद्देश्य ऐसा कोई पूर्ण या सार्वभौमिक नियम निर्धारित करना नहीं था जैसा कि वे पहली नज़र में प्रतीत होते हैं। सिंचाई विभाग बनाम अभदुता जेना तक देश की लगभग सभी अदालतों ने वाद के लंबित रहने तक का ब्याज देने के लिए मध्यस्थ की शक्ति को बरकरार

रखा था। निरंतरता और निश्चितता कानून की अत्यंत वांछनीय विशेषता है। सिंचाई के मामले में देश की लगभग सभी अदालतों ने 18 तक मध्यस्थ की शक्ति को बरकरार रखा था।

(V) वादकालीन ब्याज मूल कानून का विषय नहीं है, जैसे कि संदर्भ (पूर्व-संदर्भ अवधि) से पहले की अवधि के लिए ब्याज। पक्षों के बीच पूर्ण न्याय करने के लिए, इस तरह की शक्ति का हमेशा अनुमान लगाया गया है।"

44. उपरोक्त विचार को ध्यान में रखते हुए, हम सोचते हैं कि निम्नलिखित सही सिद्धांत है जिसका इस संबंध में पालन किया जाना चाहिए:-

जहां पक्षों के बीच समझौता ब्याज देने पर रोक नहीं लगाता है और जहां एक पार्टी ब्याज का दावा करती है और वह विवाद (मूल राशि के दावे के साथ या स्वतंत्र रूप से) मध्यस्थ को भेजा जाता है, उसके पास वाद लंबित ब्याज देने की शक्ति होगी। यह इस कारण से है कि ऐसे मामले में यह माना जाना चाहिए कि ब्याज पक्षों के बीच समझौते का एक निहित शर्त थी और इसलिए जब पक्ष अपने सभी विवादों को मध्यस्थ के पास भेजते हैं या विवाद को ब्याज के रूप में संदर्भित करते हैं, तो उसके पास ब्याज देने की शक्ति होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक मामले में मध्यस्थ को आवश्यक रूप से वाद लंबित रहने तक का ब्याज का भुगतान करना चाहिए। न्याय के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों के का प्रयोग किया जाना उसके विवेकाधिकार के भीतर एक मामला है।"

32. इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **भारत संघ बनाम अम्बिका निर्माण** के मामले में, **(2016) 6 एस. सी. सी. 36 में रिपोर्ट** किया गया।

33. दूसरे शब्दों में, एक मध्यस्त लंबित स्थिति मे ब्याज दे सकता है जब समझोता ब्याज का प्रावधान नहीं करता है या ब्याज देने पर रोक नहीं लगता है।

34. हालाँकि, वर्तमान मामले में यद्यपि विशेष शर्तों के खंड 1.9 में एक विशिष्ट प्रावधान का अनुबंध है। अनुबंध की विशेष शर्तों का खंड 1.9 निम्नानुसार हैः-

> **"1.9:विवाद आदि के कारण भुगतान में देरी के लिए कोई दावा नहीं।**
>
> आवधिक या अंतिम भुगतान करने में प्रभारी अभियंता के बीच किसी भी विवाद, अंतर या उसकी समझ के कारण सरकार के पास पड़े किसी भी धन या शेष राशि के संबंध में ब्याज या हर्जाने के किसी भी दावे पर सरकार द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।"

35. दूसरे शब्दों में, एक विशिष्ट शर्त है जो ब्याज के किसी भी दावे को रोकती है।

36. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा मत है कि जहां तक ब्याज के देने का संबंध है, उसे संशोधित करने की आवश्यकता है। विद्वान मध्यस्थ ने निर्णय की तिथि तक 18% की दर से ब्याज दिया है, जो हमारा मानना है कि उसके क्षेत्राधिकार या शक्तियों में नहीं था, विशेष रूप से समझौते के विशिष्ट खंडों को देखते हुए, जिन्हें पहले ही ऊपर संदर्भित किया जा चुका है। इसलिए, उस अवधि तक प्रतिवादी को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। विद्वान मध्यस्थ ने पहले ही फैसले की तारीख से भुगतान होने तक 6% की दर से ब्याज भी दिया है। हम उस हिस्से को भी संशोधित करते हैं, क्योंकि ब्याज केवल डिक्री की तिथि से दिया जा सकता है। अवार्ड और आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया है कि अब प्रतिवादी को डिक्री की तारीख यानी 10.05.1996 से उसके भुगतान तक केवल 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा।

37. हमारे उपरोक्त निष्कर्ष और तर्क के संदर्भ में अपील की आंशिक रूप से अनुमति है, प्रतिवादी डिक्री की तिथि 10.05.1996 से , मध्यस्थ द्वारा 5,08232/- (पाँच लाख आठ हजार दो सो बत्तीस) राशि पर 6% की दर से ब्याज का हकदार होगा।

(रमेश चंद्र खुल्बे, जे.) **(सुधांशु धूलिया, जे.)**

11.03.2019

बलवंत/सुखबंत